Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VI, Issue XI,July - 2013, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

बढ़ता आवासीय क्षेत्र और घटता कृषि रकबा एक बडी चुनौती

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VI, Issue XI, July - 2013, ISSN 2230-7540

बढ़ता आवासीय क्षेत्र और घटता कृषि रकबा एक बडी चुनौती

B. R. Bhaskar[1] Smt. Tara Bhaskar[2]

[1]Asst. Principal Arts, Govt. College Multai, Distt. Baitul

[2]Asst. Principal Arts, Govt. College Multai, Distt. Baitul

----------♦----------

समस्या :–

निःसंदेह आज भी भारत गांवो में ही बसता है। लगभग 68.84 प्रतिषत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रो में निवास कर रही हैं, किन्तु 1981 के बाद 2011 तक तीन दषको में गांवो से नगरो की ओर लोगो के पलायन से जनसंख्या की प्रवृति गांव से नगरो की ओर उन्मुख होने की रही है जिस कारण देष में षहरीकरण जोर पकड रहा है। आज देष के प्रत्येक 4 व्यक्तियो में से एक व्यक्ति षहर में रहता है जबकि 1921 में 9 में से एक व्यक्ति शहरी था। शहरो में जनसंख्यां के केन्द्रीयकरण की इस प्रवृति ने गन्दी बस्तियो का विस्तार, पर्यावरण प्रदूषण, आवासो की समस्या, बिजली पानी की समस्या, यातायात संबधी समस्या, तथा सधन जनसंख्या घनत्व ने कई प्रकार की सामाजिक और नैतिक समस्याए पैदा कर दी है। वर्तमान में महानगरो और छोटे शहरो का तेजी से विस्तार हो रहा है। आज ऊपजाउ कृषि भूमि खेती की बजाय आवासीय कालोनियो के उपयोग में ली जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, सडको, रेलो, सार्वजनिक भवनो, तालाबो, बहुउद्देषीय परियोजनाओ, बांधो, स्टाप डेम इत्यादि में भी कृषि भूमि तेजी से अधिग्रहित की जा रही है, परिणामतः 1951 में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.48 हेक्टेयर थी वह 1991 में घटकर 0.16 हेक्टे. हो गई तथा 1935 तक इसके घटकर 0.08 हेक्टेयर हो जाने की संभावना है। इस तरह कृषि भूमि का रकबा घटता ही चला जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नो की मांग सतत बढती ही जा रही है ऐसी स्थिति में सीमित कृषि रकबे से बढती खाद्यान्नो की आपूर्ति कैसे संभव होगी ? आज हमारे समक्ष यह एक बडी चुनौती है। कृषि भूमि से हमें न केवल मानव जीवन के लिए अति आवष्यक खाद्यान्नो की आपूर्ति होती है, बल्कि कृषि क्षे.त्र हमारे देष का लोगो को सर्वाधिक रोजगार प्रदायक क्षेत्र है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। अतः भू–प्रबंधन और नियोजन समय की मांग है। भारत में कृषि आधारित उद्योगो की बहुलता है ऐसी स्थिति में कृषि का महत्व और भी बढ जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्वि औद्योगिक विकास में सहायक होती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि की मात्रा भी घटती जा रही है जो आज हमारे लिए एक बडी समस्या एवं चुनौती है। यदि कृषि फेल होती है, तो हमारे देष की अर्थव्यवस्था भी फेल हो जायेगी ।

परिचयः–

रोटी, कपडा और मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। आदिकाल से ही मानव अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता की आपूर्ति खेती से करता आया है। प्राकृतिक ससाधनो में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है । कृषि एवं उद्योगो की स्थापना भूमि पर ही होती है तथा मानव व सभी जीव जन्तुओ का निवास भी भूमि पर ही होता है। इसका अन्य विकल्प हमारे पास नहीं है। मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक खाद्यान्न भूमि से ही प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के कल्याण हेतु निःशुल्क प्राकृतिक उपहार है जैसे जैसे जनसंख्या बढ रही है भूमि की मांग और महत्व भी बढता जा रहा है आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न कार्यो में इस बहुमूल्य संसाधन का उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि अधिकाधिक लोगो को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके ।

बढती हुई जनसंख्या के लिए उत्तरोत्तर खद्यान्न की मांग भी निरन्तर बढती जा रही है। शहरो एवं महानगरो से सटी ऊपजाउ कृषि भूमि आवासीय कालोनियो के लिए निजी बिल्डरो द्वारा तथा स्थानीय आवश्यकताओ के लिए प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। आवास हेतु बढती जा रही भूमि की मांग एवं शहरो से गांवो की ओर रोजगार शिक्षा व्यापार व्यवसाय आर्थिक समृद्धि और उच्च जीवन स्तर एवं भौतिक सुख सुविधाओ का उपभोग करने की लालसा से हो रहे लोगो के पलायन के कारण आवासीय उदेश्य से विगत कुछ दशको में शहरो तथा महानगरो से लगी भूमि की मांग बहुत अधिक बढ गई है परिणामस्वरूप भूमि की कीमते आसमान छू रही है और बिल्डरो भू–माफिया और निवेशको के लिए यह आकस्मिक लाभ प्रदान करने वाला व्यवसाय बन गया है। आज स्थिति यह है कि निवेशक प्लाट मकान और आवासीय भूमि में अपनी बचत को निवेशित करना पसंद कर रहे है क्योकि अल्प समय में ही भूमि की कीमते दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। अतः निवेशको को अच्छा आकस्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है और नगरीय विस्तार के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र नगरीय बस्ती के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। यह स्थिति हमारे लिए एक बडी चुनौती बन गया है।

भारत में लगभग 50 प्रतिशत परिवार निम्न एवं मध्यमवर्गीय है आवासीय भूमि के निरन्तर बढते दाम निर्माण कार्य की बेतहासा बढ़ती लागते और मंहगाई के कारण इन वर्ग के परिवारो के लिए स्वयं का घर तो आज एक सपना मात्र रह गया है। 2003 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 78 मिलियन लोग बेघर है। मनुष्य के लिए एक उपयुक्त आवास होना बुनियादी आवश्यकता है। हमारे देश में एक ओर तो बेघर लोगो की भीड़ लगी है तो दूसरी ओर कुछ सम्पन्न लोग भूमि की खरीद फरोख्त कर शहरो में बडी बडी कालोनिया बसाकर मोटा मुनाफा कमाने में लगे है जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है।

यद्यपि खाद्यान्न आपूर्ति का मूल स्त्रोत भूमि है। जिसका कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी बदलती जीवनशैली की भौतिक आवश्यकताओ की आपूर्ति के लिए बढते

www.ignited.in

औद्योगीकरण, और उत्तरोतर बढती जनसंख्या के आवास हेतू भूमि की मांग भी बढती जा रही है इसके अलावा कृषि उत्पादन बढाने के लिए सिंचित रकबा बढाने की भी आवश्यकता है। अतः बहुउदेश्यीय परियोजनाओ, बांधो, स्टाप डेम आदि में भी तेजी से भूमि डूब में जा रही है। द्रुत आर्थिक विकास के लिए अद्योसंरचना का विकास, रेल, सडक, सार्वजनिक भवन इत्यादि के लिए भी भूमि की मांग निरन्तर बढती ही जा रही है। अतः आधुनिक जीवन शैली की विभिन्न आवश्यकताओ की मांग के कारण कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है।

समाज में प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने तथा अपनी कार्यकुशलता को बनाये रखने में रोटी कपडा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति होना अति आवश्यक ही नही है बल्कि यह मनुष्य का मौलिक अधिकार भी है। आज प्रत्येक मनुष्य संतुलित पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन, हवादार और रोशनी युक्त एक उपयुक्त आवास चाहता है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे इसके लिए उपयुक्त कपडो की मांग करता है, किन्तु व्यापक आर्थिक विषमता गरीबी और बेरोजगारी के कारण आजादी के 65 वर्षो बाद भी हमारे देश के करोड़ो लोग रोटी, कपडा और मकान, शुद्ध पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओ से वंचित है।

भारत गांवो और किसानो का देश है। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण और कृषि प्रधान है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अधोसंरचना का विकास अपर्याप्त है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध न होने के कारण ग्रामो से शहरो की ओर पलायन हो रहा है, परिणामस्वरूप बडे शहरो में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इससे अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं खडी हो रही है। इस प्रकार आवास के लिए बढती जा रही भूमि की मांग एक बडी समस्या बन गया है। शहरो में आवासीय भूमि के बढते दाम और आवासीय क्षेत्र के निरन्तर होते जा रहे विस्तार के फलस्वरूप घटते जा रहे कृषि के रकबे ने हमे सोचनीय स्थिति में पहुंचा दिया है ।

2011 की जनगणना अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड है , 2020 तक इसके बढकर 1 अरब 37 करोड तथा 2050 तक 1 अरब 61 कराड 38 लाख हो जाने की संभावना है। अतः बढती हुई जनसंख्या के लिए हमे भविष्य में और अधिक खाद्यान्न और आवास हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता होगी । इस विषम परिस्थिति से हम कैसे निपटेंगे ? इस हेतु वर्तमान में देश में उपलब्ध भूमि उपयोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, भावी खाद्यान्न की मांग और आवास हेतु भूमि की भावी मांग आदि पहलुओ का गहन अध्ययन तथा विश्लेषण कर भू उपयोग के संदर्भ में उचित नीति निर्धारित करनी होगी।

परिकल्पना :–

उत्तरोतर तीव्र गति से देश की बढ़ती जा रही जनसंख्या के लिए पहले से अधिक आवासो की आवश्यकता है। भविष्य मे आवासो के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ते जाने की संभावना है। गांवो से शहरो की ओर लोगो के पलायन से नगरो की जनसंख्यां एवं जन धनत्व में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बढती नगरीय जनसंख्या ने शहरो में न केवल आवास की समस्या पैदा की बल्कि अनेक अन्य समस्याए जैसे गन्दी बस्तियो का विकास पर्यावरण प्रदूषण यातायात की समस्याओ को भी जन्म दिया है । अतः जो कृषि भूमि आवासीय भूमि में तेजी से परिवर्तित होती जा रही है। आज हमारे समक्ष यह स्थिति एक चुनौती बन गयी है।

शोध प्रविधि :–

बढता आवासीय क्षेत्र और घटते कृषि रकबे की समस्या को समझने के लिए वर्तमान भूमि उपयोग पैटर्न, नगरो के विस्तार, उपलब्ध कृषि योग्य भूमि, खाद्यान्नो की मांग, गरीबी, नगरीय जनसंख्या संबंधी द्वितीयक समंक तथा पत्र–पत्रिकाओ में प्रकाषित मान्यता प्राप्त संस्थाओ की रिपोर्ट आदि की सहायता से विभिन्न सांख्यिकीय विधियो और द्वितीयक समंको का विष्लेषण कर नगरीय जनसंख्यां के प्रतिषत, घनत्व एवं प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि इत्यादि का अनुप्रयोग कर उक्त समस्या के कारणो को जानने और समाधान हेतु सुझाव खोजने का प्रयास किया जावेगा ।

शोध के उददेश्य :–

1 महानगरो, छोटे शहरो एवं गांवो में तेजी से हो रहे आवासीय विस्तार के फलस्वरूप उपजाऊ कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन की प्रवृति को जानना।

2 घटते कृषि रकबे के कारण खाद्यान्नो की वर्तमान एवं भावी मांग की आपूर्ति हेतु गहन खेती कियाकलापो को अपनाने से उत्पन्न समस्याओ को जानना और उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

3 विगत कुछ दषको में ग्रामीण क्षेत्रो से शहरो की ओर हो रहे लोगो के तीव्र पलायन से शहरो में जनसंख्या के केन्द्रीयकरण से उत्पन्न समस्याओ को जानना और उनके उचित समाधान खोजना ।

4 बढ़ते आवासीय क्षेत्र और घटते कृषि रकबे से उत्पन्न समस्याओ की गंभीरता की ओर लोगो का ध्यान आकर्षित करना।

भारत में भू उपयोग की स्थिति

किसी देष के विकास में वहां के प्राकृतिक संसाधनो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य को प्रकृति से निःषुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। भूमि से हमे न केवल जीवनोपयोगी खाद्य पदार्थ ही प्राप्त होते है बल्कि देष के औद्यौगिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांष उद्योगो को कच्चे माल की आपूर्ति भूमि से ही होती है। अतः एक समय विषेष पर किसी देष का भू–उपयोग पैटर्न इस संसाधन के सदुपयोग को निर्धारित करता है । संसाधनो के उचित और कुषलतम उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है और विकास की गति को भी तीव्र किया जा सकता है। अतः देष में भूमि उपायो को जानना आवष्यक हो जाता है :–

भूमि उपयोग का तात्पर्य :–

भूमि उपयोग का अर्थ यह है कि किसी देष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विभिन्न उपयोगो में किस प्रकार वर्गीकृत है अर्थात कितने भू–भाग पर कृषि होती है तथा इसका कितना भाग गैर कृषि कार्यो यथा – भवनो के निर्माण, सडको, रेलो, औद्योगिक विकास कार्यो और अन्य विकास कार्यो में प्रयुक्त किया जा रहा है तथा कितना क्षेत्र रेगिस्तानी और वनाच्छादित है।

भारत में भूमि का आकार एवं उपयोग :–

भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेंत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सातवा बडा देश है किन्तु निरन्तर बढती हुई जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थिति असंतोषजनक है क्योकि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भाग 2.4 प्रतिशत है जबकि विश्व की जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भारत में है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्यां का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा 2011 की जनगणना अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया है। जबकि विश्व की जनसंख्या का घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का औसत 0.3 हेक्टेयर है।

राज्य सभा में घटती कृषि भूमि के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दोरान विभिन्न सदस्यो द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के जवाब में कृषि राज्य मंत्री अरूण यादव ने यह कहां कि देश में कृषि योग्य भूमि धटने की बात को स्वीकार करते है किन्तु इसका खाद्यान्न के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पडा है उन्हाने बताया कि समूचे देश में कृषि योग्य भूमि 2005–06 में 18 करोड 27.4 लाख हेक्टेयर थी जो 2008–09 में घटकर 18 करोड 23.8 लाख हेक्टेयर रह गई है। अतः कृषि योग्य भूमि का रकबा मामूली घटा है। इससे खाद्यान्नो के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा है। उन्होने कहा कि 2005–06 में कृषि उत्पादन 20 करोड 86 लाख टन था। वह 2010–11 में बढकर 23 करोड 20.7 लाख टन दूसरा अग्रिम अनुमान हो गया है । विभिन्न सदस्यो ने कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यो के लिए बढ़ते उपयोग पर रोक लगाये जाने की मांग के संदर्भ में कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र की ओर से कई उपाय किये गये है। इसमें राष्टीय कृषि नीति 2007, राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति 2007 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में नीति इत्यादि प्रमुख है।

म0प्र0 में कृषि क्षेत्र घटा :–

खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन के दावो के बावजूद म0प्र0 में कृषि का क्षेत्र 1.59 प्रतिषत घट गया है। राज्य के सकल जोत क्षेत्र में केवल 36.22 प्रतिषत हिस्से में ही सिंचाई सुविधा है। यह स्थिति राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड से गौरवान्वित हाने वाले म0प्र0 के लिए बडी चिन्ता का विषय है।

उद्योग एवं वाणिज्य संघ (फिक्की) द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट –

आगामी 10 वर्षो में शहरीकरण की रफ्तार बढने के कारण शहरी इलाको में 50 करोड लोगो को घरों की जरूरत पडेगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत मे आगामी दशक मे शहरीकरण की रफ्तार जोर पकडने की उम्मीद है। ग्रामो से शहरो की ओर बढते पलायन की वजह से अगले 10 वर्षो मे 50 करोड लोगो को घरों की जरूरत पडेगी तथा शहरीकरण की यह रफ्तार आगे भी जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। फिक्की ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या बढकर 1.7 अरब हो जायेगी। तथा 90 करोड लोग शहरी इलाको मे रहने के लिये आयेगें। इन लोगो के लिये आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए शहरी इलाको मे घरो के निर्माण मे चौगुणी बढोत्तरी करनी होगी इतनी बढी संख्या मे घरो का निर्माण करना हमारे लिये एक बडी चुनौती होगा। इसके अलावा सभी के लिये बिजली पानी की आपूर्ति करना कठिन कार्य होगा तथा कचरा निकासी की समुचित व्यवस्था कर पाना भी मुश्किल कार्य होगा।

(नई दुनिया भोपाल दिनांक 07.02.12 पृ. 11)

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या –

वर्ष	जनसंख्या (करोड मे)		जनसंख्या का प्रतिशत	
	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1901	2.56	20.73	11	89
2001	28.5	74.2	27.8	72.2
2011	37.7	83.3	31.16	68.84

उपरोक्त आंकडो से स्पष्ट होता है कि 1901 में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगो का प्रतिशत 11 था जो 2011 में बढकर 31.16 हो गया हैं 1901 में नगरीय आबादी 2.59 करोड थी वह 2011 में बढकर 37.7 करोड हो गई इस तरह विगत 110 वर्षो में नगरीय आबादी 14.55 गुना बढ गयी है । अतः गांवो से शहरो की ओर लोगो का तेजी से पलायन हो रहा है जिस कारण शहरो में आवास की समस्या जटिल होती जा रही है और शहरो का विस्तार भी तेजी से हो रहा है । आवास, उद्योगो तथा अन्य विकास कार्यो में कृषि भूमि तेजी से जा रही है और कृषि का रकबा घटता जा रहा है चूकि कृषि से ही हमें खाद्यान्नो की आपूर्ति होती है । अतः हमारे समक्ष आज बढती हुई जनसंख्या के लिए और अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति कर पाना एक बडी चुनौती है। इसका समाधान हमे ढूंढना ही होगा अन्यथा आगामी पीढी को इसका खामियाजा चुकाने के लिए के लिए तैयार रहना होगा।

योजना आयोग ने वर्ष 1973–74 से 1993–94 तक के गरीबी रेखा के नीचे रह रही जनसंख्या एवं वर्ष 1999–2000 के राष्ट्रीय सेंपल सर्वेक्षण द्वारा दिये गये आंकडो को निम्न तालिका मे दर्शाया गया है –

भारत मे गरीबी का अनुमान –

वर्ष	कुल जनसंख्या मे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो का प्रतिशत		
	ग्रामीण	शहरी	संपूर्ण देश
1973–74	56.4	49.0	54.9
1977–78	53.1	45.2	51.3
1983–84	45.7	40.8	44.5
1987–88	39.1	38.2	38.9
1993–94	37.3	32.4	36.0
1999–2000	27.09	23.62	26.1
2009–10	33.8	20.9	29.8

❖ अप्रैल 2002 मे योजना आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत की है रिपोर्ट मे कहा गया है कि गरीबी कम जरूर हो रही है किंतु उसकी गति बहुत धीमी है ?

❖ विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार वर्ष 2000 मे निर्धन व विकासशील देशो की कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। और इन देशो की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या अति निर्धन थी।

आजीविका एवं आर्थिक विकास का आधार कृषि :–

कृषि भारत की कुल जनसंख्या के 58.4 प्रतिशत से अधिक लोगो की आजीविका का मुख्य साधन है। कुल निर्यात का 10 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है, अनेक उद्योगो को कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि पर संकट न केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी कृषि अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भू उपयोग पैटर्न –

- वन क्षेत्र – 23 प्रतिशत
- चराई भूमि – 3 प्रतिशत
- कृषि उपयोग – 46 प्रतिशत
- बंजर भूमि – 14 प्रतिशत
- कृषि योग्य बंजर भूमि – 6 प्रतिशत
- शेष परती भूमि – 8 प्रतिशत

गैर कृषि कार्यो में प्रयुक्त भूमि –

भारत में गैर कृषि कार्यो में प्रयुकत होने वाली भूमि का विवरण –

- 1950–5193 लाख हेक्टेयर
- 1960–611 करोड 48 लाख हेक्टेयर
- 1993–94 1 करोड 80 लाख हेक्टेयर

भूमि पर जनसंख्या का बढता भार –

हमारे देश में जनसंख्या निरंतर तीव्र गति से बढती जा रही है परिणामस्वरूप भूमि पर जनसंख्या का भार भी निरंतर बढता जा रहा है। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति औसत भूमि की उपलब्धता भी सतत् घटती जा रही है इसके लिये हमें प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता पर एक दृष्टि डालनी होगी जो कि निम्नानुसार है –

वर्ष	भूमि की उपलब्धता हेक्टेयर	विश्व का औसत प्रति व्यक्ति हेक्टे.
1921	0.80 हेक्टेयर	
1931	0.72 हेक्टेयर	
1941	0.64 हेक्टेयर	
1951	0.75 हेक्टेयर	
1961	0.30 हेक्टेयर	4.5 हेक्टेयर
1971	0.29 हेक्टेयर	
1985	0.15 हेक्टेयर	
1993	0.38 हेक्टेयर	
वर्तमान	0.08 हेक्टेयर	

(स्त्रोत आर्थिक समीक्षा 2004–05, इंडियन एग्रीकल्चर इन ब्रीफ 26 वा संस्करण)

औसत जोत का घटता आकार –

भारत में 1970–71 में जोत का औसत आकार 2.3 हेक्टेयर था जो कि 1990–91 तक घटकर 1.55 हेक्टेयर यहा तक की कुल कार्यशील जोतो मे 59 प्रतिशत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम था इस प्रकार बढती जनसंख्या पारिवारिक विघटन तथा आय कई कारणो से कृषि जोत का आकार घटता जा रहा है और लागते बढ रही है कृषि निरंतर अनार्थिक होती जा रही है और लागते बढने के कारण लाभ घटता जा रहा है । जिस कृषि को पहले उत्तम माना जाता था उससे अब किसानो को मोह भंग होता जा रहा है। जो भावी खाद्यान्न संकट उत्पन्न कर सकता है।

बढ़ते आवासीय क्षेत्र एवं घटते कृषि रकबे से उत्पन्न समस्याएं :–

नगरो एवं गांवो में बढ़ते आवासीय क्षेत्र संबंधी उपलब्ध स्थितियो का अध्ययन और द्वितीयक समंको का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हमारे सामने जो समस्याए उबर कर आती है वे निम्न है :–

1 आवासीय क्षेत्र बढ़ने से देश में गन्दी बस्तियो का निरन्तर विस्तार होता जा रहा है।

2 शहरो में मकान किराये में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ।

3 आज शहरों में 100 वर्ग फुट मे पूरा परिवार रहने के लिए मजबूर है जबकि 100 वर्गफुट केवल दो व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे रहने के कारण लोगो की कार्यक्षमता घटती है और इसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पडता है।

4 सरकार का प्रशासकीय व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

5 वर्ष 1901 में नगरो की संख्या 1827 थी जो 1991 तक बढकर 3768 हो गई तथा 1911 में नगरीय जनसंख्या वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत 0.03 था। जो 1991 तक बढ़कर 3.09 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार गांवो से शहरो की ओर लोगो के पलायन ने शहरो में न केवल आवास संबंधी समस्याए पैदा की बल्कि कई अन्य समस्याओ को भी जन्म दिया है जैसे :– बढ़ती जनसंख्या हेतु अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमने

www.ignited.in

गहन खेती प्रणाली को अपनाया जिसके अन्तर्गत रासायनिक खाद, कीटनाशक, कृषि में आधुनिक यंत्रो आदि का प्रयोग किया जा रहा है । किंतु अप्रशिक्षित किसानो द्वारा अत्यधिक मात्रा में अविवेकपूर्ण ढंग से कीटनाशको के प्रयोग से फल सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ विषाक्त होते जा रहे है जिसका मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है । विभिन्न प्रकार के रसायनो के प्रयोग से भूमि की प्रकृति गुणवत्ता एवं उत्पादकता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है और इन कृषि क्रियाकलापो से भूमि, जल वायु आदि के प्रदूषण की समस्या वर्तमान में एक बडी चुनौती बन गया है।

6 शहरो मे आवासीय विस्तार एवं जन सघनता के कारण यातायात की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

7 भारत में भूमि उपयोग पेटर्न अथवा भू–उपयोग का ढांचा दोषपूर्ण है।

8 1951 में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.48 हेक्टेयर थी, जो 1991 में घटकर 0.16 हेक्टेयर रह गई तथा 2035 तक घटकर मात्र 0.08 हेक्टेयर रह जाने की सम्भावना है। अतः घटता कृषि भूमि का रकबा और भविष्य में बढती खाद्यान्न की मांग से निपटना हमारे लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य होगा ।

9 घटता वन क्षेत्र पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण हैः–

आवास एवं कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए मानव ने वनो की बेरहमी से कटाई की जिस कारण विगत 3 दशको मे वनो के क्षेत्रफल में 230 लाख हेक्टेयर की कमी आयी है। इसके अतिरिक्त सडक रेल बांध निर्माण आवासीय कालोनियो के विस्तार औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति हेतु खदानो के निर्माण आदि के लिए भी वनो की कटाई की गई परिणामतः हमारे पास वन क्षेत्र मात्र 23.3 प्रतिशत ही रह गया है जो की राष्ट्रीय लक्ष्य के 33 प्रतिशत से काफी कम है। वनो का घटता क्षेत्रफल जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की कमी का एक कारण है । स्थिति यह है कि अब कृषि भूमि का विस्तार संभव नही है और पर्यावरण संतुलन के वनारोपण और संरक्षण आवश्यक है और आवास हेतु भूमि का होना भी आवश्यक है अतः आज पर्यावरण को संरक्षित करते हुए सभी के लिए आवास और खाद्यान्न उपलब्ध कराना हमारे समक्ष एक बडी समस्या है।

10 यद्यपि विगत कुछ दशको मे हरित कांति के कारण खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग पांच गुना बढकर 25 करोड टन तक हो गया है। यह मात्रात्मक वृद्धि मात्र है । यदि खाद्यान्न उत्पादन की तुलना जनसंख्या से की जाय तो, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि देश में खाद्यान्नो की आपूर्ति आवश्यकता से कम ही है। यह तथ्य प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता से स्पष्ट हो जाता है । 1950 में 395 ग्राम 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 469 ग्राम थी जो 1965 में 480 ग्राम 1984 में 438 ग्राम और 1999 में 467.5 ग्राम हो गई इस प्रकार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की दृष्टि से हमने कोई विशेष उपलब्धी हासिल नही की है आज हम भले ही 25 करोड़ टन तक खाद्यान्नो का उत्पादन कर रहे है लेकिन यह निश्चित तौर पर नही कहा जा सकता है कि भविष्य में भी हम इतना उत्पादन कर लेंगे क्योकि असंतुलित पर्यावरण, गिरता भूजल स्तर, प्राकृतिक प्रकोप, निरन्तर कम होती जा रही भूमि की उर्वरता जैसी कृषि क्षेत्र की बडी चुनौतियां हमारे समक्ष है।

सुझावः–

1 उपजाऊ कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यो हेतु अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए ।

हमारे देश की सरकारे गैर कृषि कार्यो के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण करती जा रही है जिस कारण कृषि भूमि का रकबा घटता जा रहा है अतः निकट भविष्य में इसका खाद्यान्न उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाना होगा।

2 ग्रामीण क्षेत्रो में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि ग्रामो से शहरो की ओर लोगो का पलायन रूक सके।

3 कम आय वर्ग के लिए गृह निर्माण मंडल एवं अन्य संस्थाओ द्वारा अधिकाधिक आवास सुविधाए उपलब्ध कराई जाए।

4 ग्रामीण क्षेत्रो में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि गांवो में अधिकाधिक नवीन रोजगार अवसर सृजित हो सके।

5 यथा संभव विकास कार्यो के लिए पड़ित अथवा कम उपजाऊ भूमि के उपयोग को प्राथमिकता दी जाये।

6 वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर समयानुरूप भू–उपयोग ढांचे मे परिवर्तन किया जाना चाहिएं ताकि भूमि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अतः भारत के दोषपूर्ण भू–उपयोग ढांचे में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है।

7 प्रायः यह देखने मे आता है कि बीमारियां एवं अपराध गंदी बस्तियां मे पनपते है शहरों का एक बडा भू–भाग झुग्गी झोपडियों ने घेर रखा है। लगभग 500 से 1000 वर्ग फुट की झुग्गियों मे एक परिवार रहता है। हमारे आसपास के शहर यथा :– भोपाल इंदौर जबलपुर होशंगाबाद बैतूल छिंदवाडा जैसे नगरों मे लगभग 150 से 300 वर्गफुट की झुग्गियों मे एक परिवार निवास करता है। इस प्रकार छोटे नगरो में 10 परिवार मिलकर 8 से 10 हजार वर्गफुट की भूमि घेरते है जबकि बडे नगरो में 2000 से 3000 वर्गफुट मे दस परिवार रहते है। यदि 10 परिवारों द्वारा घेरे गये भूमि के क्षेत्रफल को खाली कराकर फ्लेट सिस्टम वाले तीन मंजिला निवास बना दिये जाये तो उतनी ही जगह मे 60 परिवार गुजारा कर सकते है। इसी प्रकार बड़े शहरों मे उतनी ही जगह में 18 परिवार निवास कर सकते है। इस प्रकार उतनी ही जगह में अधिक परिवारो को बसाकर गंदी बस्तियों का उन्मूलन कर झुग्गी वासियो का पुनर्वास किया जाता है तो उतनी ही जगह मे छोटे शहरों मे वर्तमान मे झुग्गीयो में निवासरत परिवारो की तुलना में 6 गुणा तथा बडे शहरों मे 2 गुणा अधिक परिवार समाहित हो सकते है।

निष्कर्ष :–

निःसंदेह विगत कुछ वर्षो में गांवो एवं शहरो का विस्तार तेजी से हुआ है। यदि हम म.प्र. के कुछ प्रमुख शहर भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को ले अथवा शहरो से लगे ग्रामो के विस्तार को देखे तो हम पाते है कि विगत तीन दशको में इनका बसाहट क्षेत्र लगभग 4 से 10 गुणा तक बढ गया है । बडे शहरो में तो नये नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए अद्योसंरचना के विकास हेतु रेलो और सडको का जाल बिछाया जा रहा है। कृषि विकास और अधिक खाद्यान्न उत्पादनके लिए नये नये बांध बनाए जा रहे है एवं जल संरक्षण हेतु जगह जगह स्टाप डेम बनाए जा रहे है। अतः आवासीय क्षेत्र एवं विकास कार्यो में तेजी से उपजाउ कृषि भूमि जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भविष्य में खाद्यान्न की मांग बढना सुनिश्चित ही है अतः बढती खाद्यान्न की मांग की आपूर्ति हमारे लिए समंस्या न बन जाए इसके लिए वर्तमान भूमि उपयोग पैटर्न को हमें बदलना ही होगा क्योकि खाद्यान्न हमें उपजाउ भूमि से ही प्राप्त हो सकता है इसका अन्य कोई विकल्प हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अतः समय रहते हमें उचित भू–उपयोग की दिशा में ठोस नीति का निर्माण कर कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। भू–प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए इसके कुशलतम एवं इष्टतम उपयोग को सुनिश्चिम करना ही होगा अन्यथा भविष्य में खाद्यान्न संकट से जूझने के लिए तैयार रहना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – ए.एन. अग्रवाल, 28वां संस्करण, 2002।

2. भारत 2010 – प्रकाशन विभाग,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

3. आर्थिक समीक्षा – (स्त्रोत आर्थिक समीक्षा 2004–05, इंडियन एग्रीकल्चर इन ब्रीफ 26 वा संस्करण)

4. भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ. सुदामा सिंह, डॉ. राजीव कृष्ण सिंह, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, पंचम संस्करण 2007।

5. आधुनिक भारत का वृहत भूगोल – डा. चतुर्भुज मामोरिया एवं डा. एम एस सिसौदिया

6. जनसंख्या प्रदूषण और पर्यावरण –हरिशचन्द्र व्यास विद्या विहार नई दिल्ली –2

7. समाचार पत्र–पत्रिकाए आदि ।

8. आर्थिक सर्वेक्षण 1984–85 च.106,2011.–12

9. भारतीय कृषि की आधुनिक प्रवृतियां – डां ओ पी शर्मा सबलाइम पब्लिकेषन जयपुर संस्करण 2005